



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 437]
No. 437]

मई विल्सो, मंगलवार, सितम्बर 26, 1978/आश्विन 4, 1900
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1978/ASVINA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्घोग मंत्रालय
(शोधोगिक विकास विभाग)
आवेदा
मई विल्सो, 26 सितम्बर, 1978

का० आ० 568 (भ) — (भ) / 18 ए ए/८० वि० वि० आ०/78—
भारत सरकार के भूतपूर्व उद्घोग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (शोधोगिक विकास विभाग) के आवेदा सं० का० आ० 545 (भ) / 18 एफ० वी०/आई० डी० आर० ए० / 75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्घोग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि:—

(क) उक्त प्रधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रधिनियम-सितियां, मैसेसें सेन ऐल लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से, शात शोधोगिक उपकरण को लागू नहीं होगी।

(ख) सभी संविवाहों, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, अवस्थापत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का, जो प्रवृत्त हैं प्रवर्तन जिसमें उक्त उपकरण एक पक्षकार है, या जो उस आवेदा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व लागू हो और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भव या उद्भूत होने वाली सभी अधिकारी विसेधाधिकारी वाप्तात्मा और वायित्य 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेंगे।

656 GI/78

और उक्त आदेश की प्रवधि को 26 सितम्बर, 1978 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार, का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की प्रवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए;

गत: अब, केन्द्रीय सरकार, उद्घोग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आवेदा की प्रवधि 26 सितम्बर, 1978 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है के लिए और बढ़ाती है।

[सं० फ० 2/ (21) / 75- सी० म० सी०]
पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi the 26th September, 1978

S.O. 568(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 545(E)/18FB/IDRA/75 dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section

(1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that :—

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertaking known as Messrs. Sen Raleigh Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of that Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1978 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 26th September, 1979.

[File No. 2/21/75-CUC]
P. C. NAYAK, Jt. Secy.